Refinery is exporting products to Bangladesh also. Sir, they are not only making profit, in social life, in economic life of people of Assam, they also play a very important role, and the Government of India recently invested thousands of crores of rupees for expansion and development of Numaligarh Refinery. Not only that, Sir, Numaligarh Refinery has a planning. From by-product of bamboo, they want to make some oil products. So, in the interest of the country, this refinery is very important.

My request is the Government is, please respect the sentiments of people of Assam. At least, don't privatise the Numaligarh Refinery because recently the Government of India has decided to invest near about four thousand crores of rupees for the expansion of the Numaligarh Refinery. Thank you, Sir.

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I would also like 10 associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha.

De-recognition of NIOS-D.El.Ed. degree

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और खास तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उस दौर में NIOS से D.El.Ed. की डिग्री का काफी प्रचार-प्रसार किया गया। इसमें तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी निकले। अब कहा जा रहा है कि यह in-house वालों के लिए था, जबकि विज्ञापन में ऐसा कहीं नहीं था और मुक्त विद्यालय से हुआ। अब कहा जा

[प्रो. मनोज कुमार झा]

रहा है कि उनका नियोजन नहीं हो सकता। इसलिए मैं उनकी पीड़ा साझा करना चाहता हूँ। पूरे देश में ऐसे 14 लाख अभ्यर्थी और बिहार में तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी सिर्फ अभ्यर्थी नहीं हैं, परिवार हैं। अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है, खामी है, तो वह ancillary course की व्यवस्था कर ले, bridge course की व्यवस्था कर ले, ताकि नियोजन में जो दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत की भरपाई की जा सके। साक्षरता मिशन के तहत शिक्षा प्रेरक का मसला है। बिहार में बीसियों हजार और पूरे देश में 5 लाख शिक्षा प्रेरक हैं। मैं सरकार से सिर्फ यह दरख्वास्त करूँगा कि वह इस पर संजीदगी से विचार करे। यह 44 लाख बच्चों का मामला है और हमारी शिक्षा की प्राथमिकता का मामला है। अगर इसको फौरी तौर पर नहीं किया गया, तो कई राज्यों में नियोजन चल रहा है, जहाँ यह संभव नहीं हो पाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी दरख्वास्त और अपील पुन: मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देता हूँ, ताकि ये बच्चे, जो धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए जूझ रहे हैं, वे एक सकारात्मक पहल देख सकें। शुक्रिया सर।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री माजीद मेमन (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नारायण दास गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती मीशा भारती (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्री सभापति: श्रीमती छाया वर्मा। मैडम, आपको संक्षेप में बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस विषय पर मोतीलाल वोरा जी और पी.एल. पुनिया जी को भी बोलना है।

Refusal by the Central Government to purchase surplus from Chhattisgarh

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): सर, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का चावल केन्द्रीय पूल से नहीं खरीदा जा रहा है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करना चाहती हूँ कि 2017 और 2018 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो नियमों में शिथिलता लाकर वहाँ का चावल केन्द्रीय पूल से खरीदा गया, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से नियमों में शिथिलता बरतते हुए अभी भी वहाँ का चावल खरीदा जाए। मैं सदन को बताना चाहूँगी कि इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री भी सबसे मिल चुके हैं, वे खाद्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मैं स्वयं खाद्य मंत्री जी से मिल चुकी हूँ।

लेकिन वे यह कहते हैं कि नियम नहीं है। चूंकि आप छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपये के समर्थन मूल्य पर धान खरीद रहे हैं, इसलिए हम आपका चावल नहीं खरीदते। यह किसानों के साथ अन्याय है। किसानों के साथ छल हो रहा है। यह बहुत ही निन्दनीय है। मैं सदन से पूछना चाहूंगी कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों से अलग है? आप मध्य प्रदेश का चावल खरीद रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चावल खरीद रहे हैं, बाकी सभी राज्यों से चावल खरीद रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का चावल क्यों नहीं खरीद रहे हैं?

श्री सभापति: ठीक है, श्री मोतीलाल वोरा जी।

श्रीमती छाया वर्मा: आप नियमों की बात करते हैं? जब आपको उद्योग लगाना होता है, तब तो आप आदिवासियों की जमीन खरीद लेते हैं।

श्री सभापति: छाया जी, आपने अपना प्वाइंट अच्छी तरह प्रस्तुत कर दिया है। एक ही सब्जेक्ट पर तीन लोग बोलने वाले हैं, इसलिए प्लीज़....। आपने अपना विषय बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। श्री मोतीलाल वोरा जी।

श्री मोतीलाल वोरा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। छत्तीसगढ़ में इस बार 85 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है। हमने केन्द्र सरकार से इस बात का अनुरोध किया है कि वह 32 लाख मीट्रिक टन चावल हमसे खरीदे, लेकिन केन्द्र सरकार का जो रवैया है, वह उचित नहीं है। इनका कहना है कि हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही धान लेंगे। चूंकि आपने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने की बात कही है, यह हमको स्वीकार्य नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अपने घोषणापत्र में हमने यह बात कही थी कि हम 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदेंगे। 1 दिसम्बर से धान की खरीदी होने वाली है, लेकिन केन्द्र सरकार